

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 312/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

मेन्टोर होम लोन्स इण्डिया लि. (पूर्व में मेन्टोर इण्डिया लिमिटेड), पता- प्रधान कार्यालय मेन्टोर हाऊस,
गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री हेमराज बैरवा पुत्र श्री अर्जुन लाल बैरवा,
2. श्रीमती सुमन बैरवा पत्नी श्री हेमराज बैरवा,
3. श्री कमलेश कुमार बैरवा पुत्र श्री अर्जुन लाल बैरवा,
4. श्रीमती गडूली (गडूल) देवी बैरवा पत्नी श्री अर्जुन लाल बैरवा,
पता :- प्लॉट नं. 37, शांति विहार, गोविन्दपुरा, सीतापुरा के पास, सांगानेर, जयपुर।
5. श्री हनुमान बैरवा पुत्र श्री हरि राम बैरवा,
पता :- प्लॉट नं. 37ए, शांति विहार, इन्द्रापुरी, वार्ड नं. 37, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री सूरज शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 26.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.07.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती गडूल देवी पत्नी श्री अर्जुन लाल बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 37, शांति विहार, गोविन्दपुरा, सीतापुरा के पास, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 47.38 वर्गगज को बन्धक रख कर 05,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राची वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2018 का सखेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्राधीगणों को कुल राशि 28,80,000/- रुपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त शीत सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राची वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राधीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 28,76,840/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राधीगण को दिनांक 01.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्राधीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक सपथ प्रस्तुत कर दिया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राची वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राधी अप्राधी श्रीमती गड्डल देवी पत्नी श्री अर्जुन लाल बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 37, शोति विहार, गोविन्दपुरा, सीतापुरा के पास, सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 47.88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राची वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राची वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु साबन्दा करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



दिनांक 26.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

५४०
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर